

1.6 A

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- स्पष्ट-चनुली-कोट-बासोड मोटा आंग
पीपलगाँव नैण्ड

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चनुली
तहसील बिक्रानपुर जिला अलमोडा

अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त
उत्तराखण्ड में जनपद काशी के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (— हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमि..... हे०, वन पंचायत भूमि ०.२४७ हे०) अर्थात् कुल ०.५३३४ हे० वन भूमि का आदिवासी विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चनुली द्वारा दिनांक ११-११-०१४ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चनुली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/—
ग्राम सचिव

दीप-दीप
प्रधान

ह०/—
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत-चनुली

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

गुणदेव
प्रधान

वि० उ० अधिकारी
जिला-अलमोडा, उत्तरांचल

1.6 B

प्रपत्र-23.1

दिनांक 5/11/014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चनुली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राम राय चूरसराय	
2	राम नारायण देव राम नारायण देव	
3	श्री राम नारायण देव श्री राम नारायण देव	
4	पाना देव श्री राम नारायण देव	
5	देव नारायण देव श्री राम नारायण देव	
6	देव नारायण देव श्री राम नारायण देव	
7	विमान राम देव श्री राम नारायण देव	
8	राम नारायण देव श्री राम नारायण देव	
9	श्री राम देवी श्री राम नारायण देव	
10	श्री राम देवी श्री राम नारायण देव	
11	देव नारायण देव श्री राम नारायण देव	
12	मोहन राम देव श्री राम नारायण देव	
13	नरेंद्र राम देव श्री राम नारायण देव	
14	श्री राम देवी श्री राम नारायण देव	
15	श्री राम देवी श्री राम नारायण देव	
16	श्री राम देवी श्री राम नारायण देव	
17	श्री राम देवी श्री राम नारायण देव	
18	श्री राम देवी श्री राम नारायण देव	
19	श्री राम देवी श्री राम नारायण देव	
20	श्री राम देवी श्री राम नारायण देव	

(2) श्री राम नारायण देव श्री राम नारायण देव = श्री राम नारायण देव
 श्री देवकी देवी श्री राम नारायण देव = श्री देवकी देवी
 श्री मोहन देवी श्री राम नारायण देव = श्री मोहन देवी
 श्री राम देवी श्री राम नारायण देव = श्री राम देवी
 श्री राम देवी श्री राम नारायण देव = श्री राम देवी
 श्री राम देवी श्री राम नारायण देव = श्री राम देवी
 श्री राम देवी श्री राम नारायण देव = श्री राम देवी
 श्री राम देवी श्री राम नारायण देव = श्री राम देवी
 श्री राम देवी श्री राम नारायण देव = श्री राम देवी
 श्री राम देवी श्री राम नारायण देव = श्री राम देवी
 श्री राम देवी श्री राम नारायण देव = श्री राम देवी

ह0/-
 ग्राम प्रधान
 देव नारायण देव
 प्रधान
 ग्राम पंचायत-चनुली
 वि०ख० भिव्यासैन (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में सरपदा-चनुली-कोटा-बासोहर
मो. मंडी का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सरपदा / चनुली

तहसील राजपुर जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरपदा-चनुली-कोटा-बासोहर परियोजना के निर्माण हेतु (.....
..... हे० आरक्षित वन भूमि हे० सिविल सोयम भूमि ०.२५० हे० वन पंचायत भूमि ०.२८७ हे०) अर्थात् कुल ०.५३७
हे० वन भूमि का कोटा विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सरपदा / चनुली द्वारा दिनांक ५-११-१४ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का इनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सरपदा / चनुली के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कोटा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत-चनुली
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुखर सहित

देवेंद्र सिंह
ग्राम प्रधान
मुखर सहित
0. 08. 2014

दिनांक 1-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सरपट/चनुली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	कुमार सिंह	श्री कुवर सिंह
2-	दुर्गा देवी	श्रीमती दुर्गा देवी
3-	शिव सिंह	श्री शिव सिंह
4-	कृपाल सिंह	श्री कृपाल सिंह
5-	दिवा ना सिंह	श्री दिवाना सिंह
6	दुर्गा देवी	श्री देवगिरी



1. दिवाना सिंह

श्री दिवाना सिंह

श्री दिवाना सिंह

ग्राम प्रधान / सरपंच

श्री दिवाना सिंह

प्रधान

ग्राम पंचायत-चनुली

वि० सं० निवासीन (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद-अल्मोड़ा में सरपरा - चुनौली - कोश बाखोट मोटर
मार्ग का नव निर्माण (0.537 हे०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम इनोली
तहसील भिकियासेन जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

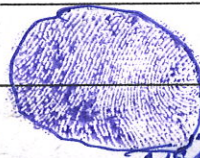
उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत इनोली परियोजना के निर्माण हेतु (X)
हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सोयम भूमि 0.25 हे० वन पंचायत भूमि 0.287 हे० अर्थात् कुल 0.537
हे० वन भूमि का को० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत इनोली द्वारा दिनांक 4-11-04 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम इनोली के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रारक्षित वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत विषय
नियमित कार्य प्रियदर्शन

ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत इनोली
महेश सिंह
वि०ख०-भिकियासेन (अल्मोड़ा)

दिनांक 4-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत इनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दीवान सिंह	दीवान सिंह
	किशनानंद	किशनानंद
	प्रमाण सिंह	प्रमाण सिंह
	दामोदर	दामोदर
	नन्दन गिरी	नन्दन गिरी
	मधुली देवी	 म० दे०

मधुली देवी

ग्राम प्रधान / सरपंच


प्रधान

ग्राम पंचायत इनोली
वि० सं० ०-भिकियासेन (अल्मोडा)

परियोजना का नाम :-

जनपद-अल्मोड़ा में सरपरा - चुन्नी - कोयल बाखोट मोटर
मार्ग का नव निर्माण (0.537 हे०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम

कुवाड़ा / इन्नेली

तहसील भिकियासैन

जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उ.प्र.रा.प.रा. परियोजना के निर्माण हेतु (X)
हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सोयम भूमि 0.250 हे० वन पंचायत भूमि 0.287 हे० अर्थात् कुल 0.537
हे० वन भूमि का क्षेत्र विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

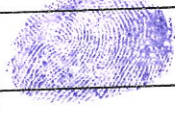
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुवाड़ा द्वारा दिनांक 4-11-04 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुवाड़ा / इन्नेली
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत कुवाड़ा / इन्नेली
अल्मोड़ा जिला

ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत कुवाड़ा / इन्नेली
अल्मोड़ा जिला
वि०ख०-भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रारूप - 23.1

दिनांक 4-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कुण्डसरा / इनोली

क्र.सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	खुशाल सिंह	खुशाल सिंह
2.	जमन सिंह	जमन सिंह
3.	मधुली देवी	
4.	विमला देवी	विमला देवी
5.	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह

ग्राम प्रधान / सम्पन्न
Prin
प्रधान

ग्राम पंचायत इनोली
वि०ख०-भिकियासैन (अल्मोडा)

परियोजना का नाम :-

जनपद-अल्मोड़ा में सम्पदा-चनुली-कोटा-वासीट मोहर
मार्ग का नव निर्माण ८०.५३७ हे०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सौर
तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत इपरोवत परियोजना के निर्माण हेतु (X)
X हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सोयम भूमि ०.२५० हे० वन पंचायत भूमि ०.२४४ हे० अर्थात् कुल ०.५३४
हे० वन भूमि का को० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सौर द्वारा दिनांक 12-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौर के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को० नि० नि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत
अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत सौर
मुख्य भिकियासैण (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

सरपंच का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपंच - चतुली - कोटा - बासोटा
मोटर मार्ग
का) नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 02-11-014 को ग्राम पंचायत सौर की बैठक आहूत की गयी, जिसमें सरपंच - चतुली - कोटा - बासोटा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन पंचायत सौर की भूमि व वृक्ष प्रभावित होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मार्ग का निर्माण शीघ्र कर लिया जाय।

सदस्य

- 1- पुष्पा देवी
- 2- प्रताप सिंह
- 3- शान्ति देवी
- 4- मि. अ. रमली देवी
- 5- रवीम सिंह

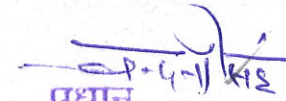
सरपंच

Kishan Singh
सरपंच
वन पंचायत सौर
वि० ख० भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रारूप -23.1

दिनांक 2-11-014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सोर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	शमसिंह S/o इन्दु सिंह	वागसिंह
2-	राजेश सिंह S/o बचें सिंह	राजेश सिंह
3-	राजेन्द्र राम S/o हरी राम	राजेन्द्र राम
4-	अम्बा देवी W/o चन्दन सिंह	अम्बा देवी
5-	शमसिंह S/o आन सिंह	शम सिंह
6-	देव सिंह S/o उत्तम सिंह	देव सिंह


प्रधान
ग्राम प्रधान / सरपंच
वि०स० भिकियासैन (अन्मोडा)

Kheem Singh
सरपंच
ग्राम पंचायत सोर
वि०स० भिकियासैन (अन्मोडा)

परियोजना का नाम :-

जनपद - सोनी में सरपंच - चबुली - जोरा - वासोरा मोटर
मार्ग का नव निर्माण 20.537 हे०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोटा गिराई
तहसील मिर्जापुर जिला सोनी
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद सोनी के अन्तर्गत प्रयोक्ता परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....X हे० आरक्षित वन भूमि 0.250 हे० सिविल सोयम भूमि 0.287 हे० वन पंचायत भूमि 0.537 हे०) अर्थात् कुल 0.537
हे० वन भूमि का कोटा निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटा गिराई द्वारा दिनांक 4-11-14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटा गिराई के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कोटा निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत
कोटा गिराई
सोनी

संगीत देवी
ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत
कोटा गिराई
सोनी

दिनांक 4-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कोटा गिरवाई

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रेवली देवी	रेवली देवी
2-	राधा देवी	राधा देवी
3-	लीला देवी	लीला देवी
4-	जीवन सिंह	जीवन सिंह

ग्राम प्रधान / सरपंच

जीवन सिंह

ग्राम पंचायत कोटा गिरवाई
80 भिकियासैण (अल्मोड़ा)

16C

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- सरपदा - चनुली, कोरा - सलोनी, पीपलगाँव बैठक तक
लिंक मार्ग,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, मि. किशोर सिंह

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, मि. किशोर सिंह

जी. एस. बिष्ट

सदस्य जिला पंचायत

24 बिनोली मिक्यासेन

जिला अल्मोड़ा

उपखण्ड स्तरीय समिति के अन्तर्गत उपखण्ड
(मि. किशोर सिंह) हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमिहे०

वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.५३७ हे० वन भूमि) का

प्रो. ए. ए. नयिपाव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मि. किशोर सिंह) की दिनांक ३-११-०१५ को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री प्रो. ए. ए. नयिपाव उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उप जिलाधिकारी,

मिक्यासेन (अल्मोड़ा)

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| श्री <u>प्रो. ए. ए. नयिपाव</u> | उप जिलाधिकारी | <u>मि. किशोर सिंह</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>वी. के. सिंह</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>मि. किशोर सिंह</u> | सदस्य |
| 3- श्री <u>मृग. एस. ए. ए. ए. ए.</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>मि. किशोर सिंह</u> | सदस्य |
| 4- श्री <u>जोगा सिंह</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>मि. किशोर सिंह</u> | सदस्य |

जोगा सिंह

सदस्य

उप जिलाधिकारी

मिक्यासेन (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

सरपदा - चनुली - कोरा वामोरे

परियोजना हेतु ०.५३७ हे० वन

भूमि

सरपदा - चनुली - कोरा वामोरे मोरु मार्ग

मि. किशोर सिंह प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मि. किशोर सिंह द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6 D.

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मि. मिश्रा परिक्षेत्र के अन्तर्गत
स. 142 - प. 200 - कोटा - 11142 परियोजना के निर्माण हेतु
हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- मि. मिश्रा
जनपद- अजमेर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- मि. मिश्रा
जनपद- अजमेर

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग। (8.50 किमी.)

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि० 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में सरपटा चनुली कोटा बासोट मोटर मार्ग (8.50 किमी.) के निर्माण हेतु 5.37 है० वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

हो/-
जिलाधिकारी

1.69

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date 04-12-2014.....at time.....at Almora. in which application claiming rights of Basot, Chanuli area measuring hect. for the Construction of Sarpata- Chanuli- Keta Basot motor Road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

04.12.14
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा. Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

1.6. H

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.537 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलमोड़ा

✓✓✓✓✓
06.12.14
जिला अधिकारी
बलमोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

1:6 17

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :.....

Dated:.....

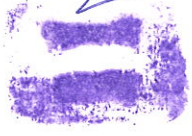
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 0.53.7 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sarpata Chanuli Kata Basat notar Road (Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Chanuli village(s) in Bhikunastan Tehsils.

It is further Certified that:

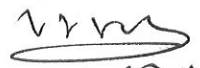
- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.53.7 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

105


 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 बलमोड़ा

13/11/14
 जिला अधिकारी,
 बलमोड़ा
 जिला समाज कल्याण अधिकारी,
 बलमोड़ा


 04/12/14
 जिला अधिकारी
 बलमोड़ा
 D.M.

Signature
 (Full name of the official seal of the District Collector)